राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग
खाद्य भवन, भू–तल, शासन सचिवालय, जयपुर–302005

राज्य कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 29.6.2011 का कार्यवाही विवरण

मानूसन वर्षा 2011 से राज्य के कुछ जिलों में बाढ़/अतिवृष्टि से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा करने हेतु मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में राज्य कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 29.6.2011 को आयोजित की गई, जिसमें उपस्थित अधिकारियों की सूची परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।

बैठक के प्रारम्भ में शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग ने राज्य में अब तक हुई वर्षा का पूर्ण विवरण प्रस्तुत किया। दिनांक 28.6.2011 तक राज्य में 37.6 मिमी सामान्य वर्षा के विरुद्ध 99.17 मिमी वर्षा हुई है, जो कि सामान्य वर्षा से लगभग 164 प्रतिशत अधिक है। राज्य के पूर्वी भागों में अभी तक अच्छी वर्षा हुई है एवं कोटा संभाग में, विशेषकर बारां जिले में बाढ़ की स्थिति भी उत्पन्न हुई है। राज्य में अब तक हुई वर्षा से खरीफ फसल की बुवाई के कुल लक्ष्य, 149.26 लाख हेक्टेयर, के विरुद्ध लगभग 10 प्रतिशत भाग में बुवाई का कार्य पूरा हो चुका है।

शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग ने यह भी अवगत करवाया कि बारां जिले में छबड़ा व छीपाबड़ौद की स्थिति संवेदनशील है, सड़क यातायात प्रभावित है, रेल यातायात चल रहा है। जिले मे आरएसी के 24 जवान राहत व बचाव कार्य में लगे हुये हैं। उन्होंने यह भी अवगत करवाया कि उनकी जिला कलेक्टर, बारां से इस सम्बन्ध में पूरी बात हो चुकी है। उन्होंनें राज्य सरकार से आरएसी के 20 जवान, 2 नावें राहत व बचाव कार्य के लिये शीघ्र भिजवाने हेतु निवेदन किया है। इसके अतिरिक्त एक चिकित्सा दल, एक पशु चिकित्सा दल, क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों के पुनरुद्धार हेतु रुपये 1.00 करोड़, पशुओं की मृत्यु व हानि के लिये रुपये 10.00 लाख व खोज व बचाव कार्यों के लिये रुपये 5.00 लाख की मांग जिले द्वारा की गई है। शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता ने यह भी अवगत करवाया कि इस समय विभाग के पास एसडीआरएफ में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है तथा जिले को उसकी मांग के अनुसार बजट उपलब्ध करवाया जा रहा है। जिला कलेक्टर ने सूचित किया है कि क्षति का पूर्ण आकलन, जल स्तर घटने के बाद, किया जाकर राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जायेगा। जिले में एनएचएआई तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग को सड़कों की मरम्मत का कार्य शीघ्र प्रारम्भ करवाने की आवश्यकता है।

शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता द्वारा आरएसी की ओर से इस जिले में किये जा रहे राहत व बचाव कार्यों का विवरण प्रस्तुत किया एवं उनके द्वारा की गई जरूरी उपकरणों की मांग भी समिति के समक्ष प्रस्तुत की।

अतिरिक्त मुख्य सचिव, जल संसाधन एवं जन स्वा. अभि. विभाग ने अवगत करवाया कि बारां जिले में पेयजल आपूर्ति प्रभावित हुई है एवं जिले के कुछ स्थानों में पीने का पानी उपलब्ध करवाने में कठिनाई उत्पन्न हुई है। विभाग द्वारा डिवाटरिंग तथा चिकित्सा विभाग के माध्यम से पानी में दवा डालने का कार्य करवाये जाने पर जोर दिया।

स्थानीय निदेशक, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने राज्य में अब तक हुई वर्षा तथा आगामी वर्षा की भविष्यवाणी पर एक विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया। उन्होंने यह अवगत कराया कि राज्य के पूर्वी भागों में अच्छी वर्षा होगी एवं पश्चिमी भाग में अपेक्षाकृत कम वर्षा होने की

संभावना है। उनके द्वारा यह जानकारी भी दी गई कि जयपुर में डोपलर राडार स्टेशन शीघ्र ही स्थापित होने जा रहा है तथा जैसलमेर में भी इसे स्थापित करने की योजना है; जिसके लिये जैसलमेर में 10–15 बीघा भूमि उनके विभाग को आवंटित किये जाने का प्रकरण जिला कलेक्टर कार्यालय में विचाराधीन है। आवंटन शीघ्र कराया जावे ताकि राज्य में मौसम संबंधी भविष्यवाणी की अधिक कारगर सुविधा उपलब्ध हो सके।

उत्तर पश्चिम रेलवे के चीफ ब्रिज इंजीनियर ने समिति को अवगत करवाया कि अभी तक की स्थिति रेलवे प्रशासन के नियंत्रण में है एवं रेलवे द्वारा अतिवृष्टि/बाढ़ की स्थिति का सामना करने हेतु सभी आवश्यक कदम उठाये जा चुके हैं एवं आवश्यक सामग्री का स्टॉक किया जा चुका है।

भारत संचार निगम लिमिटेड के जनरल मैनेजर (ओ.) ने अवगत करवाया कि उनके द्वारा भी अतिवृष्टि/बाढ़ की स्थिति में संचार व्यवस्था कायम रखने हेतु पूरे प्रबन्ध किये गये हैं।

अतिरिक्त महानिदेशक (आर्म्ड बटालियन) द्वारा भी समिति के समक्ष अपनी तैयारियों से अवगत करवाया एवं स्थिति से निपटने हेतु किये जा रहे प्रयासों पर प्रकाश डाला।

अन्त में मुख्य सचिव महोदय ने निम्न निर्देश प्रदान किये :–

1. बारां जिले द्वारा खोज व बचाव कार्यों हेतु आरएसी के अतिरिक्त जवान व नावें शीघ्र भिजवाई जावे तथा जिले को उसकी मांग के अनुसार बजट एसडीआरएफ मद से उपलब्ध करवाया जाये।
2. बारा जिले में पशुपालन व चिकित्सा विभाग का एक–एक दल शीघ्र भिजवाया जावे।
3. बारा जिले में एनएचएआई तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सड़कों की मरम्मत का कार्य शीघ्र पूरा किया जावे।
4. आरएसी कोटा द्वारा मांगे गये उपकरणों की समीक्षा करके उनको आवश्यक उपकरण उपलब्ध करवाये जायें।
5. शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग द्वारा रेलवे की समन्वय बैठक करवाने की कार्यवाही की जावे।

   उल्लेखनीय है कि बैठक के तुरन्त पश्चात् ही रेलवे के चीफ ब्रिज इंजीनियर एवं जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियन्ता के मध्य समन्वय स्थापित कर वार्ता भी करवा दी गई।
6. जिला कलेक्टर जैसलमेर को भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा चाही गई भूमि के आवंटन के सम्बन्ध में शीघ्र आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश प्रदान किये जावें।
7. एसडीआरएफ एवं पुलिस अधिकारियों को आपदा प्रबन्धन का प्रशिक्षण प्रदान करवाया जाये एवं इसके लिये आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग से आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जावे।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

शासन उप सचिव